खण्ड-7, अंक-1, वर्ष-2019, मु0प्र0 156-159
D.O.I.: 10.22445/avsp.v7i1.28

भारत के उच्च शिक्षा प्रणाली की ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्तता और चुनौतियां

वकार अहमद[1] एवं नेविल डीकुन्हा[2]
[1]सहायक प्रोफेसर, व्यवसाय प्रबंधन विभाग
एफएएसई, तिश्क इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कुर्दिस्तान
[2]एसोसिएट प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग
एफएएसई, तिश्क इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कुर्दिस्तान
waqar.ahmad@ishik.edu.iq, naville.dcunha@ishik.edu.iq

प्राप्त तिथि–30.08.2019, स्वीकृत तिथि–06.11.2019

सार– वैश्विक अर्थव्यवस्था के ज्ञान अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन के कारण राष्ट्रों के बीच संबंधों का पुनरुत्थान हुआ है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये परिवर्तन विशेष रूप से दिखाई देते हैं। ज्ञान अर्थव्यवस्था अधिकतर विकसित देशों तक ही सीमित है। व्यवहारिक रूप से सभी देशों पर ज्ञान अर्थव्यवस्था द्वारा बाध्य प्रतिमान के साथ, राज्यों के लिए इस अर्थव्यवस्था के बाहर रहना और अपने नागरिकों को जीवन स्तर देने के लिए लगभग असंभव हो गया है। इस सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में जीवित रहने और सफल होने के लिए, रणनीति मजबूत शिक्षा प्रणालियों के विकास को निर्धारित करती है। इस लेख का उद्देश्य आधुनिक ज्ञान अर्थव्यवस्था की मांगों के साथ–साथ सामान्य और भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में विशेष रूप से व्यक्तिगत राज्यों पर उनके प्रभाव को देखना है।

बीज शब्द– वैश्वीकरण, ज्ञान अर्थव्यवस्था, वैश्विक शैक्षिक प्रणाली, भारतीय उच्च शिक्षा

The knowledge economy and its challenges for the higher education system of India

Waqar Ahmed[1] and Neville D'Cunham[2]
[1]Assistant Professor, Business Management Department
FASE, Tishk International University, Kurdistan
[2]Associate Professor, International Relations Departmnet
FASE, Tishk International University, Kurdistan
waqar.ahmad@ishik.edu.iq, neville.dcunha@ishik.edu.iq

Abstract- Global economy's rapid transformation into knowledge economy has caused reshaping of relations between nations. These changes have been particularly visible in the field of higher education. The knowledge economy has been confined mostly to developed countries. With the paradigm shift compelled by knowledge economy on practically all the countries, it has become virtually impossible for states to remain outside this economy and give a good standard of living to its citizens. To survive and succeed in this most competitive economy, the strategy presupposes the development of strong education systems. This article aims to look at the tendencies brought along by modern knowledge economy demands and their effect on individual states in general and Indian higher education system in particular.

Key words- Globalization, knowledge economy, global educational systems, Indian higher education

1. **परिचय–** कृषि की उम्र और औद्योगिक क्रांति के प्रारम्भ से 10,000 साल बाद 1750 में मानव सामाजिक विकास, जीवन शैली, और भलाई में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत हुई। आज के डिजिटल युग में, मानव जाति एक और समान रूप से महान परिवर्तन के बीच में हो सकती है। ज्ञान अर्थव्यवस्था की उम्र पियोरोव्स्की' हमें याद दिलाती हैं, "लेकिन वास्तव में, एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता अक्सर मायावी रहता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी अभी भी कोई सहमति नहीं है। वास्तव में, यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी प्रणाली वास्तव में किसी भी सार्थक अर्थ में उपस्थित नहीं है। आखिरकार, मानव संस्कृतियों ने हमेशा जीवित रहने और अपने जीवन को बेहतर

बनाने के लिए ज्ञान पर भरोसा किया है। "फिर भी, यह स्वीकार करना होगा कि औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित ज्ञान और आधुनिक शैक्षिक प्रणाली के बीच पारस्परिक संबंध है। आधुनिक दुनिया में सभी ज्ञान सृजन शैक्षिक प्रणालियों की संभावनाओं से कम है। अपने देशों को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर धकेलने वाली सरकारों को शैक्षिक विकास को अपनी रणनीतियों के केंद्र में रखना चाहिए। इस प्रकार, यह लेख वैश्विक शिक्षा प्रणालियों के लिए अपने निहितार्थ प्रदान करता है, और विशेष रूप से भारतीय उच्च शिक्षा के संदर्भ में ज्ञान अर्थव्यवस्था, की सर्वोत्कृष्टता का पता लगाने का प्रयास करेगा।

2. **ज्ञान–अर्थव्यवस्था की अवधारणा–** ग्रिम्सली[2] के अनुसार, एक ज्ञान अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मुख्य रूप से ज्ञान–गहन गतिविधियों पर आधारित होता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में, आर्थिक विकास और रोजगार का एक बड़ा हिस्सा ज्ञान–गहन गतिविधियों का एक परिणाम है। दूसरी ओर, केंटन[3] के अनुसार, विश्व बैंक चार स्तंभों के अनुसार ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं को परिभाषित करता है–

1. संस्थागत संरचनाएं जो उद्यमिता और ज्ञान के उपयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।
2. कुशल श्रम की उपलब्धता और एक अच्छी शिक्षा प्रणाली।
3. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के बुनियादी ढांचे तक पहुँच।
4. एक जीवंत नवाचार परिदृश्य जिसमें अकादमिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज शामिल हैं।

इसलिए हम यह मान सकते हैं कि 21 वीं सदी में, ज्ञान अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई वृद्धि मूर्त वस्तुओं के उत्पादन से दूर अमूर्त या सूचनात्मक वस्तुओं के साथ–साथ सेवाओं के लिए एक बड़ी पारी का हिस्सा है। सूचना युग में, वैश्विक अर्थव्यवस्था ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गई है, जिससे यह प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था से सर्वोत्तम प्रथाओं को लेकर आया है। इसके अतिरिक्त, ज्ञान आधारित कारक एक परस्पर और वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाते हैं जहाँ ज्ञान के स्रोत, जैसे मानव विशेषज्ञता और व्यापार रहस्य, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण कारक हैं और महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन माने जाते हैं। केंटन[3] ज्ञान अर्थव्यवस्था को संक्षेप में इस प्रकार बताते हैं–

ज्ञान अर्थव्यवस्था उपभोग और उत्पादन की एक प्रणाली है जो बौद्धिक पूंजी पर आधारित है।
अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं अलग–अलग डिग्री में आर्थिक गतिविधियों की तीन प्रमुख श्रेणियों से बनी हैं: कृषि, विनिर्माण और सेवाएं।
सूचना युग में, वैश्विक अर्थव्यवस्था ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गई है, यह प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था से सर्वोत्तम प्रथाओं को साथ लेकर आई है।
ज्ञान अर्थव्यवस्था में, उत्पाद और सेवाएँ जो बौद्धिक विशेषज्ञता के आधार पर तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।

इस प्रकार, केंटन[3] द्वारा प्रस्तुत तर्क को हमारे अध्ययन के संदर्भ में व्याख्यायित किया जा सकता है क्योंकि ज्ञान अर्थव्यवस्था यह बताती है कि शिक्षा और ज्ञान, अर्थात् ''मानव पूंजी,'' एक उत्पादक सम्पत्ति या व्यावसायिक उत्पाद के रूप में सेवा कर सकता है और उपज का उत्पादन करने के लिए निर्यात किया जा सकता है। व्यक्तियों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के लिए। अर्थव्यवस्था का यह घटक प्राकृतिक संसाधनों या भौतिक योगदान के बजाय बौद्धिक क्षमताओं पर बहुत निर्भर करता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में, उत्पाद और सेवाएँ जो बौद्धिक विशेषज्ञता के आधार पर तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाती हैं, अर्थव्यवस्था में नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं। जैसा कि विश्व बैंक के आकलन से पता चला है कि ज्ञान और राष्ट्रीय विकास, इसकी आर्थिक ताकत, राजनीतिक स्थिरता और मानव संसाधन विकास के बीच अंतर्संम्बंध है। इसके अनुसार, अपने सामाजिक आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास को बनाए रखने के लिए शिक्षा की मजबूत व्यवस्था बनाने में अधिकांश आधुनिक सरकारों के निहित स्वार्थ का निरीक्षण करना आश्चर्यजनक नहीं है। इसलिए, निम्न खंड वैश्विक शिक्षा प्रणालियों के लिए ज्ञान अर्थव्यवस्था के निहितार्थ को देखेगा।

3. **ज्ञान–अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्रणाली पर इसका प्रभाव–** राजनीतिक और आर्थिक अंतर्संम्बंध के साथ वैश्वीकरण के एक युग में, ज्ञान–निर्माण की भूमिका तेज हो गई है। परिणामस्वरूप, उच्च शिक्षा के क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया गया है, जिससे यह ज्ञान अर्थव्यवस्था में केंद्र–स्तर पर आ गया है। कुशल शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से, अमेरिका, यूरोप और जापान ने दुनिया के बाकी हिस्सों में विशाल प्रतिस्पर्धी–बढ़त की स्थापना की है। फिर भी, ज्ञान अर्थव्यवस्था की अवधारणा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी तरह से आकार और अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, यद्यपि इसका प्रभाव शिक्षा प्रावधान पर जबरदस्त है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को स्थापित करने की दिशा में प्रभावी और कुशल प्रणालियों का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय सरकारों की आकांक्षाओं से प्रेरित है, जो उच्च प्रतिस्पर्धी पेशेवरों, या मानव संसाधनों को 'नस्ल' करेगा, जो देश की सफलता का निर्धारण करेगा (पॉवेल एंड स्नेलमैन[4])। ज्ञान अर्थव्यवस्था 'की अवधारणा ने कई राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को एक पारंपरिक वस्तु के रूप में उच्च शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए औचित्य प्रदान किया, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा(पॉवेल और स्नेलमैन[4], रोसेनबर्ग[5], ब्रेस्नाहन[6], हेल्पमेन[7] में उद्धृत)। शिक्षा के रूप में कमोडिटी एप्रोच के माध्यम से यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा उत्पाद कौन,

कैसे और किस कीमत पर खरीदेगा, क्योंकि यह बहुत हद तक शिक्षा व्यवसाय की सफलता को निर्धारित करेगा। जैसे–जैसे ज्ञान अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक हिस्से में फैलती है, उत्पादन के ज्ञान गहन अभ्यास बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकताओं की तुलना में अपने प्रतिभागियों की उत्कृष्ट क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए अंगर[8] हमें याद दिलाता हैः ''यह दोनों युवा और जीवन भर एक निश्चित प्रकार की शिक्षा के लिए कहता है।'' इसलिए, यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि शिक्षा या समकालीन ज्ञान अर्थव्यवस्था की मांगों की दिशा दोनों में सुधार करके इस प्रकार की शिक्षा सामान्य और तकनीकी के बीच विभाजन को पार कर सकती है।

दुर्भाग्य से, ज्ञान अर्थव्यवस्था की दुनिया भर में उपस्थिति कुलीन वर्ग के लिए बनी हुई है। इन परिस्थितियों में, "ज्ञान अर्थव्यवस्था के कारावास से संबंधित ताकतें आर्थिक स्थिरता और आर्थिक असमानता को बढ़ाने के लिए कॉन्सर्ट में काम करती हैं। उत्पादकता में वृद्धि और आर्थिक असमानता को गहरा करने की मंदी ज्ञान अर्थव्यवस्था की समझदारी के लिए मूल्य है।[8] इसलिए, पियोट्रोव्स्की[1] ने गरीब देशों को चेतावनी दी हैः "ज्ञान अर्थव्यवस्था विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ा वादा रखती है, लेकिन बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी की उपलब्धता के आधार पर, यह वादा मृगतृष्णा में बदल सकता है। ज्ञान बढ़ाने के माध्यम से आर्थिक विकास बनाने की आर्थिक विचारधारा को बिना सोचे समझे लागू नहीं किया जा सकता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में कूदने से पहले, विकासशील देश सरकारों को स्टॉक लेने और खुद से यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी प्रणाली प्राप्त करने योग्य हैं, और वास्तव में उनके देश के लिए वांछनीय है। "समकालीन दबावों के कारण, भारत ने एक विकासशील देश के रूप में 1990 के बाद का पदभार संभाला है। नीतिगत सुधारों के माध्यम से अपने सबसे चुनौतीपूर्ण भारतीय संदर्भ के अनुरूप 'ज्ञान अर्थव्यवस्था' बनने के लिए। इस प्रकार, अगले भाग में, हम भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और यह ज्ञान अर्थव्यवस्था द्वारा लाई गई चुनौतियों का सामना कैसे कर रहा है।

4. **ज्ञान–अर्थव्यवस्था और भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली–** भारत जैसे शीत युद्ध के बाद के विकासशील देशों में प्रत्येक देश के सामने चुनौती पेश की है कि वह एक सीखने वाला समाज कैसे बने और अपने नागरिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान, कौशल और योग्यता से लैस करे कि उन्हें ज्ञान अर्थव्यवस्था में जीवित रहने और सफल होने की आवश्यकता होगी। जैसा कि हेसलोप[9] की टिप्पणीः भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली मूल रूप से अभिजात वर्ग की सेवा करने के लिए निर्मित की गई है, अब लोगों की सेवा करनी होगी। प्रणाली को आने वाले दशकों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है। यह परिवर्तन आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तन द्वारा संचालित किया जा रहा हैः 2020 तक, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जिसके मध्यम वर्गों के आकार में इसी तेजी से वृद्धि होगी। नवाचार और परिवर्तन की आवश्यकता है और यह समझना आवश्यक है कि परिवर्तन आवश्यक होगा। "इसलिए, उच्च शिक्षा, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और ज्ञान अर्थव्यवस्था में सामाजिक स्थिरता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

भारत संस्थानों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है, और छात्रों की संख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। यद्यपि, शिक्षा के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद, भारत को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संपूर्ण रूप से शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता, पहुँच और इक्विटी के मुद्दों के साथ घिरी हुई है। भारत में शिक्षा का सामान्य मानक निम्न है। यह राहुल चौदहा[10] द्वारा प्रमाणित हैः "उच्च शिक्षा छात्रों, अर्थव्यवस्था और समाज पर अपने उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुधारने की सख्त आवश्यकता है। नाटकीय विकास के बावजूद भारतीय उच्च शिक्षा ने देखा है। यह विस्तार गुणवत्ता की लागत पर आया है, जिसके परिणामस्वरूप कई छात्रों ने बिना किसी प्रासंगिक नौकरी–कौशल के साथ क्रेडेंशियल्स के साथ स्नातक किया है। "भारत के लिए, शिक्षा प्रावधान में सुधार और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुशल स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों का दावा किया जाता है। संचित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का जवाब होना। इसके अतिरिक्त, यह व्यापक रूप से सहमत है कि आर्थिक विकास उच्च शिक्षा की मजबूत प्रणालियों के साथ सीधे संबंध में है। आश्चर्य नहीं कि भारत ने शिक्षा की मजबूत व्यवस्था बनाने में रुचि दिखाई है क्योंकि यह आर्थिक मुद्दों का जवाब दे सकता है और ज्ञान अर्थव्यवस्था का आधार बना सकता है।

भारत में, कल्याणकारी राज्य की समाजवादी विचारधारा ने संविधान सभा (1947–49) के विचार–विमर्श को सूचित किया क्योंकि इसने भारतीय गणराज्य का खाका खींचा। राज्य के उद्यमों और ''लाभ के लिए नहीं'' के कल्याण विचारधारा के रूप में उच्च शैक्षिक संस्थानों ने समाजवादी कल्याणकारी भारतीय राज्य की स्थापना के प्रारम्भ में काम किया है। लेकिन उनका पूर्ण कार्यान्वयन बुरी तरह से विफल रहा क्योंकि 1991 में शीत युद्ध के अंत के साथ राज्यों ने अपना रास्ता खो दिया, तत्पश्चात् पूरे वैश्विक सामरिक और आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र ने नव–उदारवाद में भारी बदलाव देखा।

नवउदारवादी राज्य के लिए वैश्विक धक्का–मुक्की के बावजूद सोशलिस्ट यूरोपियन मॉडल सबसे प्रभावशाली है। हेसलोप[9] बताते हैंः "विश्वविद्यालय की शिक्षा, कानून द्वारा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में लाभ के लिए नहीं है। वास्तविकता थोड़ी अधिक जटिल है। अधिकांश निजी संस्थान अवैध कैपिटेशन फीस के माध्यम से पैसा बनाने का एक व्यापक रूप से प्रचलित साधन संचालित करते हैं, 'छात्र द्वारा दी जाने वाली एक फीसद ऑफ–द–बुक्स के रूप में। निजी क्षेत्र का तर्क है कि कम, लेकिन वैध छात्र शुल्क पर कैप, निजी संस्थानों के लिए कैपिटेशन शुल्क के बिना काम करना असंभव बना देता है। ऐसे संकेत हैं कि सरकार तेजी से मानती है कि निजी और राज्य वित्त पोषित संस्थानों में वित्त पोषण सहायता और छात्र शुल्क के निम्न स्तर अस्थिर हैं और इसलिए भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना है।

"इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने में उम्मीदों के अनुसार वितरित करने के लिए समाजवादी यूरोपियन मॉडल विफल हो गया है।"

यदि भारत उच्च शिक्षा को ज्ञान अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखता है, तो एकीकृत करने का मुख्य तरीका अपने कार्यबल नागरिकों को वांछनीय कौशल बनाना है। उच्च शिक्षा के छात्रों द्वारा आवश्यक ज्ञान अर्थव्यवस्था कौशल में आवश्यक रूप से विश्लेषणात्मक सोच, समस्या–समाधान, महत्वपूर्ण तर्क, सहयोगी कार्य, नवाचार, रचनात्मकता और आईसीटी कौशल शामिल होना चाहिए। अंग्रेजी में प्रवीणता को छात्रों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए सबसे आवश्यक आवश्यकता माना जाता है। प्रोफेसर जेम्स ए0 बैंकों ने भविष्यवाणी कीः ''21वीं सदी में शिक्षा की भूमिका छात्रों को प्रभावी कार्रवाई में भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल विकसित करने और देखभाल करने के तरीकों को जानने, देखभाल करने और कार्य करने के लिए तैयार करना है'' (थोरात[11] में उद्धृत)। इसलिए, ज्ञान अर्थव्यवस्था द्वारा लगाए गए विभिन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए, छात्रों की ज्ञान अर्थव्यवस्था नागरिकता गठन के साथ भारतीय उच्च शिक्षा के सामंजस्य की आवश्यकता है।

5. **निष्कर्ष**– भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के सामने ज्ञान अर्थव्यवस्था की चुनौतियां इस विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से स्पष्ट हो गईं। यह पता चला कि शब्द ज्ञान अर्थव्यवस्था की सटीक परिभाषा अस्पष्ट है। लेकिन हमने अधिकांश आधिकारिक स्रोतों से आने वाली परिभाषाओं के संदर्भ में अपने काम को बेहतर बनाने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश की है। विश्व बैंक ने अपने व्यापक अनुसंधान और क्षेत्र अध्ययन के माध्यम से चार स्तंभों के एक काफी सुसंगत सैद्धांतिक मॉडल के साथ आया है। ये चार स्तंभ सभी समावेशी हैं, इस अर्थ में कि वे हमारे हर विस्तार वाले वैश्वीकृत दुनिया में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर सभी हितधारकों को शामिल करते हैं। ज्ञान अर्थव्यवस्था न केवल वैश्विक शिक्षा क्षेत्र के लिए, बल्कि निकट भविष्य के कार्यबल में शामिल होने वाले छात्रों के लिए भी निरंतर नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। ज्ञान अर्थव्यवस्था द्वारा सभी श्रमिकों के लिए पेश की गई चुनौतियों पर चिंतन करते हुए, अंगर[6] के अनुसारः ''सबसे अधिक शिक्षित आबादी के साथ, सबसे अधिक शिक्षित आबादी के साथ, कम उत्पादक नौकरियों के लिए भी, श्रम बल के विशाल बहुमत की निंदा करके उन पर विश्वास करता है। यह उन्हें कम जीवन जीने के लिए मजबूर करता है, जिससे उनकी शक्तियों के विकास और उनकी मानवता की अभिव्यक्ति को अपर्याप्त गुंजाइश मिलती है। यद्यपि, ज्ञान अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा क्षेत्र का परिवर्तन, हम कम हो रहे श्रमिकों के पारिश्रमिक के बिना उत्पादकता की उम्मीद कर सकते हैं।"

भारतीय शिक्षा के क्षेत्र के संदर्भ में, ज्ञान अर्थव्यवस्था की चुनौतियां सबसे कठिन हैं। हमारे जैसे समाजवादी लोकतांत्रिक देश में, यह हमेशा माना जाता रहा है कि आर्थिक अधिकार राजनीतिक अधिकारों के समान महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार एक दूसरे के पूरक और पूरक हैं, क्योंकि वे एक ही कार्बनिक संवैधानिक प्रणाली की मूल संरचना बनाते हैं। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए चुनौती यह है कि निजी उपक्रमों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा के स्थान को खोलने के तरीके और ''लाभ के लिए'' क्या काम किए बिना छोड़ दिया जाना चाहिए। समाजवादी राज्य अभी भी निजी उद्यमों को दबाने के बजाय, निजी संस्थानों के वितरण तंत्र पर प्रतिबंधों को कम करके या वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के साथ पूरे देश की उच्च शिक्षा को संरेखित करके भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपने आधिपत्य का संरक्षण कर सकता है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और सिविल सोसाइटी की मुख्य चुनौती होगी।

संदर्भ

1. पिओट्रोव्स्की, जे0(2015) व्हाट इज ए नॉलेज इकोनॉमी? www.scidev.net/global/knowledge-economy/feature/knowledge-economy-ict-developing-nations.html. (Accessed on 08-09-2019).
2. ग्रिम्स्ली, आर0(2017) लेटेस्ट डाटा एण्ड स्टेटिस्टिक्स ऑन हाइयर एण्ड न्यू रेगुलेटरी रिफॉर्म, *www.dreducation.com*. (Accessed on 10-11-2018).
3. केंटन, डब्ल्यू0(2019) नॉलेज इकोनॉमी, www.Investopedia.com/terms/k/knowledge-*economy.asp*. (Accessed on 08-09-2019).
4. पॉवेल, डब्ल्यू0 डब्ल्यू0 एवं स्नेलमैन, के0(2004) द नॉलेज इकोनॉमी, एनवल रिव्यू सोशियल0, खण्ड–30, मु0पृ0 199–220।
5. रोजेनबर्ग, एन0(1982) इनसाइड द ब्लैक बॉक्स–टेक्नोलॉजी एण्ड इकोनॉमिक्स, कैब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. ब्रेस्नाहन, टी0 एफ0 एवं ट्रैज्टेनबर्ग, एम0(1995) जनरल परपज टेक्नोलॉजीजः इंजिन्स ऑफ ग्रोथ? ज0 इकोनाम0, खण्ड–65, मु0पृ0 83–108।
7.हेल्पमेन, ई0(1998) जनरल परपज टेक्नोलॉजीज एण्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, कैम्ब्रिज, एम0ए0ःएम0आई0टी0 प्रेस।
8. अंगर, आर0 एम0(2019) द नॉलेज इकोनॉमी, *KNOWLEDGE-ECONOMY. pdf*. (Accessed on 07-09-2019).
9. हेसलॉप, एल0(2018) अंडरस्टैंडिंग इण्डियाः द फ्यूचर ऑफ हाइयर एजुकेशन एण्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इण्डिया, न्यू दिल्ली, भारत।
10. चौदहा, राहुल(2017) लेटेस्ट डाटा एण्ड स्टेटिस्टिक्स ऑन हाइयर एजूकेशन एण्ड न्यू रेगुलेटरी रिफॉर्म्, *www.dreducation.com*. (Accessed on 10-11-2018).